e-newsletter
issue XXII Aug., 2016

CMAR

City Managers' Association Rajasthan

Promoting excellence in city management ...

SmartCity

CMAR

e-Newsletter Issue XXIIth June, 2016

Editor - in Chief : **Shri Purushottam Biyani (IAS)**
(Director cum Joint Secretary, LSGD, GoR)

Editorial Team & Compilation : **Dr. Himani Tiwari**
(Coordinator, CMAR)
Mr. Sharawan Kumar Sejoo
(Research Assistant, CMAR)

Digital Typesetting : **Mr. Arjun Pal**
(IT Expert, CMAR)

CMAR Team : **Mr. Sandeep Nama**
(Research Investigator, CMAR)
Mr. Sitaram Verma
(Assistant, CMAR)

OUR SINCERE THANKS TO

- **Smt. Sanchita Bishnoi (RAS)** (Add. Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Smt. Preeti Mathur (RAS)** (Project Director, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri Hulas Ray Pawar (R.Ac.S)** (Chief Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Smt. Madhu Rathore (R.Ac.S.)** (Sr. Account Officer, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri R.K. Vijayvagia** (Sr. Town Planner, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)
- **Shri Pankaj Kumar Mangal** (Commissioner, Bundi Municipal Council, Rajasthan)
- **Shri Brijesh Pareek** (PRO, Directorate of Local Bodies, Rajasthan)

For suggestions/feedback please write to:
City Managers' Association Rajasthan, Room. No. 410, Directorate of Local Bodies,
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur-302015
Telefax: 0141-2229966 | Web: www.cmar-india.org | Email- cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on CMAR's website at: http://cmar-india.org/

Contents

स्मार्ट सिटीज मिशन एवं अमृत योजना की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में स्मार्ट सिटी की प्रगति का ब्यौरा दिया	1
मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट सिटी जयपुर के लिए सौगातों की बरसात	3
महुआ और नापासर नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित	5
ऑन–लाईन जारी होगी भवन निर्माण स्वीकृती	6
प्रदेश की हर सिटी स्मार्ट सिटी हो यही हमारा उद्देश्य	8
फायर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अधिकृत	10
अमृत योजनान्तर्गत पंचकुला (हरियाणा) में क्षमता संवर्द्धन हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	11
Press Coverage	12

स्मार्ट सिटीज मिशन एवं अमृत योजना की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान में स्मार्ट सिटी की प्रगति का ब्यौरा दिया

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून, 2016 को स्मार्ट सिटी मिशन में कार्य शुरू होने के अवसर पर जयपुर और उदयपुर शहरवासियों को स्मार्ट सिटी में चयनित होने के लिए बधाई दी। माननीय प्रधानमंत्री इस महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा के एक वर्ष पूर्ण होने पर पुणे के छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर और उदयपुर के चयन हेतु धन्यवाद के असली हकदार यहां के निवासी हैं। इन लोगों के प्रयासों के कारण ही स्मार्ट सिटी प्रतिस्पर्धा के सभी पेरामीटर्स को समय सीमा में पूरा कराया जा सका और इन दोनों शहरों को प्रतिस्पर्धा में जीत के साथ पहले चरण के 20 शहरों में चुना गया। इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राजस्थान से जयपुर एवं उदयपुर को इस मिशन के प्रथम चरण में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राजे ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि जयपुर में आज रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने, बस शैल्टर्स में पब्लिक इन्फोरमेशन सिस्टम एवं रामनिवास बाग में नवीनीकृत सावन भादो उद्यान का शुभारम्भ किया गया। साथ ही, शहर की 14 बावड़ियों के संरक्षण एवं

जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर दक्षिण एशिया के पहले लाइटहाउस सिटी के लिए चुना गया है। इससे पिंकसिटी जयपुर हेम्बर्ग, बार्सिलोना और एडिलेड जैसे शहरों की सूची में शामिल हो गया है। श्रीमती राजे ने कहा कि सिस्को की साझेदारी से शहर में वाई–फाई हॉटस्पॉट, वीडियो सर्वेलांस कैमरा, इन्टरेक्टिव कियोस्क, रिमोट ई–गवर्नेंस समाधान एवं पार्किंग मैनेजमेंट प्रणालियों की आईटी आधारित कई सेवाओं की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर में कचरे से बिजली (Waste to Energy) बनाने के लिए पीपीपी आधार पर प्लांट लगाया जाएगा। कचरे से बिजली (Waste to Energy) का जोधपुर के लिए 400 tdp, जयपुर के लिये 600 tdp, कोटा के लिये 300 tdp, और 2018 में सुचारू रूप से कार्यरत हो जायेंगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर में धरोहर संरक्षण एवं विकास के कार्य, स्मार्ट क्लास रूम्स, रूफ टॉप सोलर प्लांट की स्थापना और कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर विकसित करने और सीवरेज के कार्य हाथ में लिए गए हैं। श्रीमती राजे ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण के लिए अजमेर और कोटा के प्रस्ताव भी तय समय से पहले केन्द्र सरकार के पास भिजवा दिए जायेंगे।

इसी प्रकार अमृत योजना की प्रथम वर्षगांठ पर योजना पर कार्यो का विस्तृत ब्यौरा दिया गया तथा राज्य की 29 अमृत योजना में चयनित निकाय द्वारा अमृत योजना की वर्षगांठ मनाई। उक्त निकायों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने की स्मार्ट जयपुर के लिए सौगातों की बरसात

माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर बिड़ला सभागार में आयोजित समारोह में जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई सौगातें दी। श्रीमती राजे ने रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने, बस शैल्टर्स में पब्लिक इन्फोरमेशन सिस्टम एवं रामनिवास बाग में नवीनीकृत सावन भादो उद्यान का उद्घाटन किया। उन्होंने गुलाबी नगर की 14 बावड़ियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास भी किया। श्रीमती राजे ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश से चयनित शहरों पर ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए चयनित शहरों में हैरिटेज, पर्यटन, स्मार्ट नगरीय ढांचे एवं सुरक्षित सड़क ढांचे का विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब जयपुर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देश का अव्वल शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि आज हम स्वच्छ भारत मिशन में भी देश में सबसे आगे हैं। प्रदेश में बीकानेर पहला खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) जिला बन चुका है। इस तरह प्रदेश के 7 जिले ओडीएफ बनने की कतार में हैं। हैरिटेज स्वरूप बनाए रखते हुए करें विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में विकास कार्यो में यह ध्यान रखा जाए कि हैरिटेज स्वरूप को बनाए रखते हुए जयपुर को आधुनिक बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि परकोटे में इमारतों के बाहरी स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करें। पर्यटक हमारी पिंकसिटी की पुरानी खूबसूरती को देखने आते हैं न कि कांच की इमारतों को। परकोटा वासियों से अपील, छतों पर सोलर प्लांट लगाएं श्रीमती राजे ने कहा कि जयपुर में ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकारी इमारतों के छत पर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। झालाना संस्थानिक क्षेत्र और जेएलएन मार्ग पर स्थित सभी सरकारी इमारतों को इसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने चारदीवारी क्षेत्र के निवासियों का आह्वान किया कि वे अपने घरों की छत पर रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाएं ताकि परकोटा क्षेत्र को बेतरतीब फैले बिजली के तारों के जाल से मुक्त कराया जा सके।

उन्होंने कहा कि शहर में जगह– जगह बिजली और केबल के तार नहीं दिखेंगे तो इसकी खूबसूरती और निखरेगी। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पर खर्च में भी कमी आएगी। शहर को साफ रखना हम सबका फर्ज मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे शहर को साफ–सुथरा और सुंदर बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबको मिलकर निभानी होगी। शहर में सड़कों पर या पार्कों पर जहां भी पॉलिथीन उड़ती दिखें तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें उठाकर कचरा पात्र में डालें। उन्होंने कहा कि जब मैं स्वयं सड़क पर कचरा देखकर अपनी कार रूकवाकर उसे साफ करवाती हूं तो आप भी इसी भावना से कार्य करते हुए अपना दायित्व निभाएं। श्रीमती राजे ने कहा कि शहर की कॉलोनियों में बने छोटे पार्कों की सार–संभाल के लिए विकास समितियों को आगे आना चाहिए। रामनिवास बाग में सावन–भादों पार्क के अलावा करीब 10 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि आमजन को समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थानों पर टिकट राजस्व वसूली के लिए नहीं बल्कि वहां साफ–सफाई एवं सुविधाओं के विकास के लिए लगाया जाता है। सड़कों पर नहीं छोड़ें पालतू पशु मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान गोपालकों से अपील की कि वे अपनी पालतू गायें एवं अन्य पशु खुले में सड़क पर नहीं छोड़ें। इससे गन्दगी तो फैलती ही है साथ ही यातायात भी बाधित होता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम यह सुनिश्चित करे कि आवारा पशु सड़कों पर नहीं घूमें और सड़कों पर पशु छोड़ने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। उन्होंने इसके लिए बड़ा जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया। महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को मिले सख्त सजा श्रीमती राजे ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले कुंठाग्रस्त लोगों के साथ सख्ती से पेश आए। उन्होंने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारी इस तरह के मामलों के त्वरित निस्तारण की व्यवस्था बनाने के बारे

में सोचें ताकि ऐसे अपराधों के दोषियों को जल्द सजा मिल सके। अम्बेडकर सर्किल के पास गाड़ी रूकवाकर कचरा हटवाया मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री निवास आते समय अम्बेडकर सर्किल के पास सड़क पर कचरा देखकर अपनी गाड़ी रूकवाई और सुरक्षाकर्मियों को अविलम्ब कचरा हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पास ही स्थित जीवन बीमा निगम की इमारत के सुरक्षाकर्मी को निर्देश देकर भवन के प्रवेश द्वार पर बिखरा कचरा हटवाया। स्मार्ट राजस्थान की दिशा में काम स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। पानी की उपयोगिता व संरक्षण के लिए चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का असर दिखने लगा है। अब सरकार स्मार्ट राजस्थान की दिशा में तेजी से काम कर रही है। महापौर श्री निर्मल नाहटा ने कहा कि जयपुर की कला–संस्कृति और हेरिटेज पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। हमारा लक्ष्य यहां की प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए शहर को स्मार्ट बनाना है। इससे पूर्व जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी. सरवन कुमार ने जयपुर स्मार्ट सिटी के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। कार्यक्रम के अंत में जयपुर नगर निगम के आयुक्त श्री हेमन्त कुमार गेरा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

महुआ और नापासर नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2009) की धारा 3 सहपठित धारा 329 एवं अधिसूचना सं.प.8(ग) ( )नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/3825–4090 दिनांक 30.04.2012 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 02/06/2016 को अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायत (महुआ) जिला दौसा तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम सं.18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत (नापासर) जिला बीकानेर को नगरपालिका चतुर्थ श्रेणी घोषित किया है। वर्तमान में राज्य के नगरीय निकायों की संख्या 190 हो गई है।

ऑन-लाईन जारी होगी भवन निर्माण स्वीकृति

स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने दिनांक 05 जुलाई, 2016 स्वायत्त शासन भवन में भवन निर्माण की प्रथम ऑन–लाईन स्वीकृती जारी की।

इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने भिवाड़ी एवं उदयपुर की दो भवन निर्माण स्वीकृतियॉ जारी कर योजना का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना का 23 जून को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया था। योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा 2 गोल्ड स्टार भी दिये गये थे। योजना को देश का सर्वोत्तम भवन निर्माण स्वीकृती सिस्टम माना गया है।

योजना के शुभारंभ के अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि यह योजना आम नागरिकों को जहाँ एक ओर राहत प्रदान करेगी वहीं दूसरी ओर भवन निर्माण स्वीकृती में पूर्ण पारदर्शिता लागू होगी। उन्होनें कहा कि पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृती में अत्यधिक समय लगता था। अब भवन निर्माण स्वीकृती सामान्य प्रक्रिया में एक माह तथा फास्ट ट्रेक स्वीकृती एक दिन में जारी हो सकेगी तथा आवेदक भवन निर्माण स्वीकृती पर की जा रही कार्यवाही को ऑन–लाईन देख सकेगा। उन्होनें बताया कि ऑन–लाईन भवन निर्माण स्वीकृती की इस प्रक्रिया को नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की समस्त संस्थाओं, नगर निगम/पालिकाओं, सभी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों के साथ–साथ रीको को भी सम्मिलित किया गया है तथा पंचायती राज्य के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रक्रिया को लागू किया जायेगा।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस

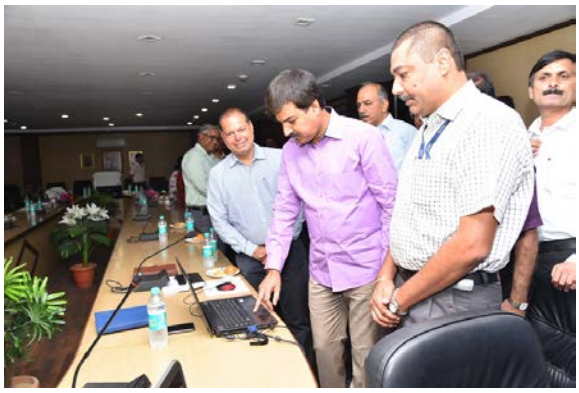

अवसर पर बताया कि केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही मे कराये गये एक अध्ययन के दौरान पता चला कि देश में भवन निर्माण स्वीकृती जारी करने में नगरीय निकायों को तीन माह से 2 वर्ष तक का समय

लगता है। इससे जहॉ एक ओर आवेदक को परेशानी का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर देश में विकास की दर भी धीमी होती है। राजस्थान सरकार द्वारा इस और पहल की गई तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृती के लिए एक ऑनलाईन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है।

उन्होनें बताया कि **ऑन–लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम सिंगल विडों क्लियरेंस सिस्टम** पर लागू किया गया है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्डिंग प्लान अप्रुवल से संबंधित समस्त प्रक्रिया को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। जिसमें बिल्डिंग प्लान का परीक्षण पत्रावली का आवेदन संबंधित नगरीय निकाय में पत्रावली का परीक्षण, विभिन्न शाखाओं के रिपोर्ट स्थल निरीक्षण, भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क एवं स्वीकृती जारी किये जाने की समस्त प्रक्रिया को ऑन–लाईन किया गया है तथा जारी की गई स्वीकृती को आर्किटेक्ट, आवेदक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति/संस्था ऑन–लाईन देख सकता है। उक्त सॉफ्टवेयर में दो प्रकार के विकल्प निर्धारित किये गये है। पहला सामान्य एवं दूसरा फास्ट ट्रैक रखा गया है तथा सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग बॉयलॉज के 42 पैरामीटर निर्धारित किये गये है। फास्ट ट्रैक स्वीकृती में आवेदक (विकासकर्ता) को एक ही दिन में निर्माण स्वीकृती दी जा सकेगी। फास्ट ट्रैक स्वीकृती के तहत यदि भवन मानचित्र बिल्डिंग बॉयलॉज के 42 निर्धारित मापदण्डों की पूर्ती करता है एवं भूमि स्वामित्व का एडवोकेट से प्रमाणित प्रमाण–पत्र ऑन–लाईन प्रस्तुत करता है एवं निर्धारित राशि जमा कराता है, तो निर्माण स्वीकृती एक दिवस में जारी की जा सकेगी। सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदित आवेदनों पर एक माह में स्वीकृती जारी की जा सकेगी।

उन्होनें बताया कि उक्त प्रक्रिया में कोई भी कार्य मैन्यूअल नहीं होगा तथा साईट विजिट भी ऑन–लाईन मोबाईल के माध्यम से हो सकेगी। उक्त प्रक्रिया के लागू होने से भवन निर्माण स्वीकृती में पूर्ण पारदर्शिता आयेगी।

प्रदेश की हर सिटी स्मार्ट सिटी हो यही हमारा उद्देश्य

स्वायत्त शासन विभाग एवं स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से (रेवेन्यू जनरेशन एण्ड प्रोक्यूरमेंट) कार्यशाला का आयोजन

प्रदेश की सभी नगरीय निकाय अपने–अपने संसाधनों से आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे। प्रदेश की हर सिटी स्मार्ट सिटी हो यही हमारा उद्देश्य है।

प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मनजीत सिंह ने यह उद्गार शुक्रवार को स्वायत्त शासन भवन में स्वायत्त शासन विभाग एवं स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित (रेवेन्यू जनरेशन एण्ड प्रोक्यूरमेंट) कार्यशाला में उपिस्थत नगरीय निकाय के अधिकारियों के समक्ष व्यक्त किये।

प्रमुख शासन सचिव डॉ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब समझाते हुए कहा कि किसी भी, शहर में वाटर सप्लाई ठीक हो, पानी का नुकसान न हो, 24 घन्टे नागरिको को पानी मिले, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर घर सीवरेज से जुड़ा हो, हर घर में शौचालय हो एव उसका उपयोग किया जाये, नगरीय निकायो द्वारा किये जाने वाले कार्य ऑन–लाईन हो, शहर का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन स्पेस विकसित हो, कचरे का प्रबन्धन हो, तभी वो SmartCity की श्रेणी में आयेगा।

उन्होने कहा कि राजस्थान की नगरीय जनसंख्या लगभग 5 करोड़ से अधिक है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश की हर नगरीय निकाय ऑन–लाईन हो तथा नागरिको को सभी आवश्यक मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हो। उन्होनें बताया कि वर्तमान में देश मे जारी केन्द्र सरकार की सभी योजनाएं चाहे स्मार्टसिटी, एल.ई.डी. लाईट, अमृत स्वच्छ भारत मिशन हो, सब में राजस्थान आगे है। प्रदेश में सभी नगरीय निकायों में प्रोपर्टी का सर्वे किया जा रहा है। सभी नगरीय निकायों मे दोहरी लेखा पद्धति से कार्य प्रारम्भ किया गया है। आने वाले समय में प्रदेश की 190 नगरीय निकाय क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर 40 हजार करोड़ रूपये व्यय किये जायेंगे।

स्मार्ट सिटी काउन्सिल इंडिया के फाउण्डर डायरेक्टर श्री प्रताप पडोडे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी शहरों में योजनाओ की क्रियान्विति के लिये SPV का

गठन किया गया है। सभी स्मार्ट सिटी के अलग–अलग चुनौतियाँ है जिनका स्थानीय तरीके से निस्तारण कर नागरिको को उच्चस्तरीय जीवन उपलब्ध करवाना है। उन्होने कहा कि स्मार्ट सिटी देश के शहरों को विकसित करने का एक नया तरीका है।

कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने वेस्टवाटर एनर्जी, वाटर मेनेजमेंट, सिक्योरिटी, मोबोलिटी, एनर्जी एफिशियेन्सी विषयो पर गहनता से चर्चा की व बेस्ट प्रेक्टीसिस बताए जिनके माध्यम से चयनित स्मार्ट सिटीज उनका उपयोग कर सकते है।

कार्यशाला में जोधपुर नगर निगम आयुक्त ने पब्लिक ट्रांसर्पोटेशन के लिए अतिरिक्त बसों एवं उनकी फ्रिक्वेन्सी बढ़ाने तथा फ्लाई ओवर निर्माण पर जोर दिया। अजमेर नगर निगम के कमिश्नर श्री डी.एस. पाण्ड्या ने कहा कि किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी सरकारी साधनों से नहीं बनाया जा सकता। इसके लिये उस शहर की जनता को जोड़ा जाना अति आवश्यक है। उन्होने बताया कि स्मार्ट सिटी के प्रथम चरण में अजमेर इसलिये चयनित नहीं हुआ क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी प्रस्तावो से जनता को नही जोड़ा गया। उन्होने बताया कि द्वितीय चरण में बनाये गये प्रस्तावो में हमने लगभग 3 लाख लोगों से सम्पर्क किया। लोगो ने अपने सुझावो में 48 प्रतिशत ने सेनिटेशन सुधार 47 प्रतिशत ने पब्लिक ट्रांन्सर्पोटेशन 47 प्रतिशत ने कचरा प्रबंधन पर तथा सेफ्टी सिक्योरिटी, वाटर सप्लाई के संबंध में प्रस्ताव दिये है।

स्मार्ट सिटीज के स्टेट नोडल अधिकारी श्री अनिल सिंघल ने बताया कि SPV के माध्यम से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को पूरा किया जायेगा। उक्त कार्य केन्द्र सरकार द्वारा दी गई गाईड लाईन के तहत पूरा होगा। यदि आवश्यकता होगी तो SPV परियोजनाओ के पूरा करने के लिए ऋण भी ले सकेगी।

फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी अधिकृत

आमजन की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए और कतिपय प्रकरणों में स्वीकृति में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी करके राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश एवं नियमों की अनुपालना में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, परमिशन, स्वीकृति पत्र आदि जारी करने हेतु नगर निगमों के मामलों में संबंधित उपायुक्त तथा अन्य निकायों के मामलों में संबंधित आयुक्त/अधिशाषी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में निर्णय लेने हेतु नगर निगमों के मामलों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी एवं अन्य नगरीय निकायों के मामलों में अग्निशमन से संबंधित अधिकारी की अभिशंषा पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी को फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। जयपुर नगर निगम में इन दिनों काम को और ज्यादा सुगम, सरल और सहज बनाने की कोशिश की जा रही है। जयपुर नगर निगम के समस्त कार्यो के विकेंद्रीकरण पर बल दिया जा रहा है। निगम में मुख्यालय स्तर पर 10 लाख रुपए तक के बिलों को स्वीकृत करने की शक्ति अतिरिक्त आयुक्त को प्रदान की गई है, वहीं अलग–अलग जोनों में इसके लिए जोन उपायुक्त को शक्ति प्रदान की गई है। अब 10 लाख रुपए तक के बिल वित्तीय सलाहकार के पास जाने के बजाय वरिष्ठ लेखाधिकारी तक ही जाएंगे। अगर जोन से लेखाधिकारी फाइल प्रस्तुत कर रहा है तो मुख्यालय पर उससे नीचे के स्तर के अधिकारी के पास पत्रावली नहीं जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया से प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्य की गति बढ़ेगी। जयपुर नगर निगम में ज्यादा से ज्यादा कार्यो के विकेंद्रीकरण का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

अमृत योजनान्तर्गत पंचकुला (हरियाणा) में क्षमता संवर्द्धन हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

PRESS RELEASE

ded. TNN

Stepwells in Bundi to get a NEW LEASE OF LIFE

Rachnasingh
@timesgroup.com

Jaipur: It's better late than never. The dying heritage of the 'City of Stepwells' is going to be revived under the Mukhyamantri Jal Swavlamban Abhiyan. The 17th to 19th century water conservation structures in Bundi, the stepwells that over the years had become garbage dump yards are now going to be resuscitated.

Bundi collector Naresh Kumar Thakral said, "These directions have come from the chief minister and two nodal departments, the nagar parishad and the PHED have been assigned the responsibility. In all 44 stepwells, 8 kunds and 2 lakes would be taken up under this initiative."

In the past, TOI, had several times highlighted that 'stepwells in Bundi lie in neglect face extinction,' and if the 'Swachh Bharat' campaign could save the stepwells of Bundi? The orphaned monuments of historical importance were once sanctuaries for bathing, praying and meditation that showcased traditional ways of water conservation. Now, there are being filled up with garbage by the day and encroached upon.

"Our first objective is to clean the 'baoris' and the 'kunds' so that they can be used as natural water reservoirs that would over a period of time recharge ground water. By the year end we plan to restore and bring back the glory of 70 per cent of the step wells," said Pankaj Mangal municipal commissioner, Bundi.

The project that has just begun cleaned up five 'kunds' and one 'baori', the 'Raniji Ki Baodi' built in 1699 so far. At the moment the municipal staff is trying to clean the 300-year-old Meera Gate Baodi, the only 'U' shaped 'baori' in Bundi, which is filled to the brim with garbage. Add to that an iron angle on one side of the 'baori' lends support to a nearby shop, standing on garbage.

"It is true for so many years nobody ever thought of cleaning up these 'baoris' and the garbage kept accumulating. When we began work at Meera Gate baori, locals started protesting and did not let us clean it. They feared once the 'baori' is cleaned then very soon we would also bring down their encroachments," said Mangal.

CLEANING-UP ACT: Meera Gate baori that was full to the brim with garbage after partial clean-up

> Our first objective is to clean the 'baoris' and the 'kunds' so that they can be used as natural water reservoirs that would over a period of time recharge ground water. By the year end we plan to restore and bring back the glory of 70 per cent of the step wells
>
> PANKAJ MANGAL | MUNICIPAL COMMISSIONER, BUNDI

OUR PARTNER'S

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ICMA
International City/Country Management Association

USAEP
United State-Asia Environmental Partnership

NIUA
National Institute of Urban Affairs

CMAR

City Managers' Association Rajasthan, Room. No. 410, Directorate of Local Bodies
G-3 Rajmahal Residency, Near Civil Lines, Railway Crossing, Jaipur - 302015,
Telefax: 0141-2229966, www.cmar-india-org, E mail-cmar.rajasthan@gmail.com

Electronic version of this newsletter is also available on the website at: http://www.cmar-india.org/